VIDYA BHAWAN BALIKA VIDYA PITH शक्ति उत्थान आश्रम लखीसराय बिहार

Class 12 commerce Sub. ECO/B Date 26.05.2021 Teacher name – Ajay Kumar Sharma

Indian Economy 1950–1990 (R.Notes)

Question 16:

Though public sector is very essential for industries, many public sector undertakings incur huge losses and are a drain on the economy's resources. Discuss the usefulness of public sector undertakings in the light of this fact.

ANSWER:

Although, the mismanagement and wrong planning in PSUs may lead to misallocation and, consequently, to wastage of the scarce resources and finance but PSUs do have some positive and useful advantages.

- **1.** *Enhancing Nation's Welfare*: The main motive of the PSU was to provide goods and services that add to the welfare of the country as a whole. For example, schools, hospitals, electricity, etc. These services not only enhance welfare of country's population but also enhance the future prospects of economic growth and development.
- **2.** Long Gestation Projects: It was not feasible and economically viable for the private sectors to invest in the big and wide projects like basic industries and electricity, railways, roads, etc. This is because these projects need a very huge initial investment and have long gestation period. Hence, PSU is the most appropriate to invest in these projects.
- **3. Basic Framework**: An important ideology that was inherited in the initial five year plans was that the public sector should lay down the basic framework for industrialisation that would encourage the private sector at the latter stage of industrialisation.
- **4. Socialist Track:** In the initial years after independence, Indian planners and thinkers were more inclined towards socialist pattern. It was justified on the rational ground that if the government controls the productive resources and production, then it won't mislead the country's economic growth. This was the basic rationale to set up PSUs. These PSUs produce goods not according to the price signals but according to the social needs and economic welfare growth of the country.
- **5.** Reduce Inequality of Income and Generate Employment Opportunities: It was assumed that in order to reduce inequalities of income, eradicate poverty and to raise the standard of living, government sector should invest in the economy via PSUs.

Question 17:

Explain how import substitution can protect domestic industry. ANSWER:

In the initial seven five year plans, India opted for import substitution strategy, which implies discouraging the imports of those goods that could be produced domestically. Import Substitution Strategy not only reduces an economy's dependence on the foreign goods but also provides impetus to the domestic firms. Government provides various financial encouragements, incentives, licenses to the domestic producers to produce domestically the import substituted goods. This would not only allow the domestic producers to sustain but also enables them to grow as they enjoy the protective environment. They need not to fear from any competition and also not to worry about their market share as license gives them the monopoly status in the domestic market. Being monopolist, they earn more profits and invest continuously in R&D and always look for new and innovative techniques. This gradually improves their competitiveness and when they are exposed to the international market they can survive and compete with their foreign counterparts.

Question 18:

Why and how was private sector regulated under the IPR 1956? ANSWER:

IPR 1956 was adopted in order to accomplish the aim of state controlling the commanding heights of economy. This policy was aligned with the Indian economy's inclination towards socialist pattern of system of Soviet Union. According to this resolution, industries were classified into following three categories:

Category 1: Those industries that are established and owned exclusively by the public sector.

Category 2: Those industries in which public sector will perform the primary role while the private sector will play the secondary role. That is, the private sector supplements the public sector in these industries.

Category 3: Those industries that are not included in Category 1 and Category 2 are left to the private sector.

These industries that were left to the private sector, the government owns an indirect control by the way of license. In order to initiate a new industry, private entrepreneurs should obtain license (or permit) from the government. By licensing system, tax holidays and subsidies government can promote industries in a backward region that will ,in turn,

promote the welfare and development of that region. This was supposed to reduce regional disparities.

Further, in order to expand the scale of production, private sector needs to obtain license from government. This was supposed to keep a check on the production of goods that are socially undesirable and unwanted. Hence, the state fully controlled the private sector either directly or indirectly.

Question 19:

Match the following:

1.	Prime Minister	A.	Seeds that give large proportion of
			output
2.	Gross Domestic	В.	Quantity of goods that can be imported
	Product		
3.	Quota	C.	Chairperson of the planning
	,		commission
4.	Land Reforms	D.	The money value of all the final goods
			and services produced within the
			economy in one year
5.	HYV Seeds	E.	Improvements in the field of
			agriculture to increase its productivity
6.	Subsidy	F.	The monetary assistance given by
			government for production activities.

ANSWER:

1.	Prime Minister	C.	Chairperson of the planning commission
2.	Gross	D.	The money value of all the final goods and
	Domestic		services produced within the economy in
	Product		one year
3.	Quota	B.	Quantity of goods that can be imported
4.	Land Reforms	E.	Improvements in the field of agriculture to
			increase its productivity
5.	HYV Seeds	A.	Seeds that give large proportion of output
6.	Subsidy	F.	The monetary assistance given by
			government for production activities.

प्रश्न 16: हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों के लिए बहुत आवश्यक है, कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भारी नुकसान होता है और अर्थव्यवस्था के संसाधनों पर एक नाली होती है। इस तथ्य के आलोक में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उपयोगिता की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुप्रबंधन और गलत योजना के कारण गलत आवंटन हो सकता है और परिणामस्वरूप, दुर्लभ संसाधनों और वित्त की बर्बादी हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक उपक्रमों के कुछ सकारात्मक और उपयोगी फायदे हैं।

- 1. राष्ट्र के कल्याण में वृद्धि: पीएसयू का मुख्य उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करना था जो समग्र रूप से देश के कल्याण में शामिल हों। उदाहरण के लिए, स्कूल, अस्पताल, बिजली आदि। ये सेवाएं न केवल देश की आबादी के कल्याण को बढ़ाती हैं बल्कि आर्थिक विकास और विकास की भविष्य की संभावनाओं को भी बढ़ाती हैं।
- 2. लंबी अविध की परियोजनाएं: निजी क्षेत्रों के लिए बुनियादी उद्योगों और बिजली, रेलवे, सड़कों आदि जैसी बड़ी और व्यापक परियोजनाओं में निवेश करना संभव नहीं था और आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं था। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन परियोजनाओं में बहुत बड़े प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है और इन परियोजनाओं के लिए बहुत अधिक प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था की लंबी अविध। इसलिए, पीएसयू इन परियोजनाओं में निवेश करने के लिए सबसे उपयुक्त है।
- 3. मूल ढांचा: शुरुआती पंचवर्षीय योजनाओं में विरासत में मिली एक महत्वपूर्ण विचारधारा यह थी कि सार्वजनिक क्षेत्र को औद्योगीकरण के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना चाहिए जो औद्योगीकरण के बाद के चरण में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगा।
- 4. समाजवादी ट्रैक: स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों में, भारतीय योजनाकारों और विचारकों का झुकाव समाजवादी पैटर्न की ओर अधिक था। यह तर्कसंगत आधार पर उचित था कि यदि सरकार उत्पादक संसाधनों और उत्पादन को नियंत्रित करती है, तो वह देश के आर्थिक विकास को गुमराह नहीं करेगी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना का यह मूल कारण था। ये सार्वजनिक उपक्रम मूल्य संकेतों के अनुसार नहीं बल्कि देश की सामाजिक जरूरतों और आर्थिक कल्याण विकास के अनुसार माल का उत्पादन करते हैं।

5. आय की असमानता को कम करना और रोजगार के अवसर पैदा करना: यह माना गया कि आय की असमानताओं को कम करने, गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, सरकारी क्षेत्र को पीएसयू के माध्यम से अर्थव्यवस्था में निवेश करना चाहिए।

प्रश्न 17:

बताएं कि आयात प्रतिस्थापन घरेलू उद्योग की रक्षा कैसे कर सकता है।

उत्तर:

प्रारंभिक सात पंचवर्षीय योजनाओं में, भारत ने आयात प्रतिस्थापन रणनीति का विकल्प चुना, जिसका अर्थ है उन वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित करना जो घरेलू स्तर पर उत्पादित की जा सकती हैं। आयात प्रतिस्थापन रणनीति न केवल विदेशी वस्तुओं पर अर्थव्यवस्था की निर्भरता को कम करती है बल्कि घरेलू फर्मों को भी प्रोत्साहन प्रदान करती है। सरकार घरेलू उत्पादकों को घरेलू रूप से आयात प्रतिस्थापित माल का उत्पादन करने के लिए विभिन्न वितीय प्रोत्साहन, प्रोत्साहन, लाइसेंस प्रदान करती है। यह न केवल घरेलू उत्पादकों को बनाए रखने की अनुमति देगा बल्कि उन्हें विकसित होने में भी सक्षम करेगा क्योंकि वे सुरक्षात्मक वातावरण का आनंद लेते हैं। उन्हें किसी प्रतिस्पर्धा से डरने की जरूरत नहीं है और न ही अपने बाजार हिस्से की चिंता करने की जरूरत है क्योंकि लाइसेंस उन्हें घरेलू बाजार में एकाधिकार का दर्जा देता है। एकाधिकारवादी होने के कारण, वे अधिक लाभ कमाते हैं और अनुसंधान एवं विकास में लगातार निवेश करते हैं और हमेशा नई और नवीन तकनीकों की तलाश करते हैं। यह धीरेधीरे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करता है और जब वे अंतरराष्ट्रीय बाजार के संपर्क में आते हैं तो वे जीवित रह सकते हैं और अपने विदेशी समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।

प्रश्न 18:

निजी क्षेत्र को आईपीआर 1956 के तहत क्यों और कैसे विनियमित किया गया था?

उत्तर:

आईपीआर 1956 को अर्थव्यवस्था की कमांडिंग ऊंचाइयों को नियंत्रित करने वाले राज्य के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनाया गया था। यह नीति सोवियत संघ की प्रणाली के समाजवादी पैटर्न के प्रति भारतीय अर्थव्यवस्था के झुकाव के अनुरूप थी। इस संकल्प के अनुसार, उद्योगों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था:

श्रेणी 1: वे उद्योग जो विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा स्थापित और स्वामित्व में हैं।

श्रेणी 2: वे उद्योग जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र प्राथमिक भूमिका निभाएगा जबकि निजी क्षेत्र द्वितीयक भूमिका निभाएगा। यानी निजी क्षेत्र इन उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र का पूरक है।

श्रेणी 3: जो उद्योग श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में शामिल नहीं हैं, उन्हें निजी क्षेत्र पर छोड़ दिया गया है।

इन उद्योगों को जो निजी क्षेत्र पर छोड़ दिया गया था, सरकार के पास लाइसेंस के माध्यम से एक अप्रत्यक्ष नियंत्रण है। एक नया उद्योग शुरू करने के लिए, निजी उद्यमियों को सरकार से लाइसेंस (या परिमट) प्राप्त करना चाहिए। लाइसेंस प्रणाली द्वारा, कर अवकाश और सब्सिडी सरकार पिछड़े क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा दे सकती है, जो बदले में, उस क्षेत्र के कल्याण और विकास को बढ़ावा देगी। यह क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने वाला था।

इसके अलावा, उत्पादन के पैमाने का विस्तार करने के लिए, निजी क्षेत्र को सरकार से लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है। यह उन वस्तुओं के उत्पादन पर नियंत्रण रखने वाला था जो सामाजिक रूप से अवांछनीय और अवांछित हैं। इसलिए, राज्य ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निजी क्षेत्र को पूरी तरह से नियंत्रित किया।